

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2604
14 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: सीड मिनी किट

2604. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:

श्री कृपानाथ मल्लाह:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने किसानों को रेपसीड और सरसों के सीड की मिनी किट निःशुल्क वितरित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि आबंटित और उपयोग की गई है;
- (ग) सीड मिनी किट के मुफ्त वितरण हेतु किन राज्यों को चुना गया है;
- (घ) क्या सरकार वैश्विक जलवायु परिवर्तन जिसका खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, से निपटने के लिए विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए परिष्कृत संकर बीजों की विभिन्न किस्मों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) वैश्विक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने में इन संकर बीजों के किस प्रकार सहायक सिद्ध होने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (

(क) से (ङ.) भारत सरकार रेपसीड और सरसों के बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) के तहत, नवीनतम जारी उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/ संकर बीजों को सामने लाना और उन्हें किसानों के बीच लोकप्रिय बनाना और उनका प्रचार और विस्तार करना है। सरकार ने सरसों उगाने वाले 15 प्रमुख राज्यों में रेपसीड और सरसों के बीज के 8.20 लाख मिनीकिट

जिलों में रबी 2021-22 के दौरान 1066.78 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आवंटित किए हैं।

रबी 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) के तहत रेपसीड और सरसों के बीज मिनीकिट के वितरण के लिए चुने गए राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा हैं। सरसों की संकर किस्मों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम-ओएस) के तहत राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के माध्यम से कुल रुपये 779.96 लाख की लागत के साथ, सरसों के 1.20 लाख संकर बीज मिनी किट वितरण हेतु प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी है।

रबी 2021-22 के दौरान एचवाईवी और संकर रेपसीड और सरसों के बीज मिनीकिट का राज्य-वार आवंटन और वितरण **अनुबंध-** 1 में दिया गया है।

सरसों में, संकर बीज जैसे सीएमएस आधारित हाइब्रिड और भारतीय सरसों की 5 किस्मों और पीले सरसों की एक किस्म के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)- रेपसीड-सरसों अनुसंधान निदेशालय (डीआरएमआर), भरतपुर, राजस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में जलवायु अनुकूल रेपसीड-सरसों की किस्मों को लोकप्रिय बनाने की पहल की गई है। जैविक एवं अजैविक प्रभावशील तथा गुणवत्ता विशेषताओं वाली इन संकर बीजों तथा किस्मों की विशिष्ट वृद्धिकारक दशाओं के लिए सिफारिश की गई है।

संकर बीजों को आईसीएआर द्वारा किसान के खेत में प्रदर्शित किया जाता है और अधिसूचित राज्यों में किसानों द्वारा इनकी खेती की जा रही है। उच्च पैदावार वाली किस्मों (एचवाईवी) की तुलना में संकर बीजों की पैदावार बेहतर होती है। रबी 2021-22 के दौरान प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात को संकर सरसों के बीज मिनी किट वितरित किए गए हैं।

रबी 2021-22 के दौरान रेपसीड और सरसों के एचवाईवी और संकर बीज मिनीकिट का राज्य-वार वितरण।

(i) रबी 2021-22 के दौरान रेपसीड और सरसों के एचवाईवी बीज की मिनीकिट के राज्यवार वितरण का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	वितरित बीज मिनीकिट (संख्या में)
1	बिहार	55625
2	छत्तीसगढ़	10200
3	गुजरात	28060
4	हरियाणा	95867
5	जम्मू और कश्मीर	8307
6	झारखंड	34950
7	मध्य प्रदेश	22980
8	ओडिशा	10000
9	पंजाब	25000
10	राजस्थान	173465
11	उत्तर प्रदेश	119525
12	उत्तराखंड	0
13	असम	10000
14	अरुणाचल प्रदेश	2000
15	त्रिपुरा	2500
योग		598479

(ii) रबी 2021-22 के दौरान सरसों के संकर बीज मिनीकिट के राज्यवार वितरण का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	वितरित बीज मिनीकिट (संख्या में)
1	गुजरात	20000
2	हरियाणा	15000
3	मध्य प्रदेश	30000
4	राजस्थान	20000
5	उत्तर प्रदेश	35000
योग		120000